इकाई 1 ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति के अध्ययन का महत्व

इकाई की रूपरेखा

1.1 प्रस्तावना

1.2 उद्देश्य

1.3 ऑस्ट्रेलिया की घरेलू शक्तियाँ

1.4 क्रियात्मक बंधुत्व के माध्यम से गठबंधन निर्माण

1.5 बहुपक्षीयता से द्विपक्षीयता की ओर

1.6 ऑस्ट्रेलिया के अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्पर्क

1.7 ऑस्ट्रेलिया के सुरक्षा सम्पर्क

1.8 ऑस्ट्रेलिया-भारत अभिसरण

1.9 सारांश

1.10 अभ्यास

1.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1.1 प्रस्तावना

दक्षिणी गोलार्ध के आधे अधोभाग में हिन्द और प्रशान्त महासागरों पर ऑस्ट्रेलिया की जो भौगोलिक अवस्थिति है, उसे देखते हुए अक्सर उसे एक "अधोस्थित" (down under) देश के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसका अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में बहुत ही कम महत्व था। किन्तु, यदि इसके इतिहास पर सरसरी तौर पर दृष्टि भी डालें, तो यह पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया एक स्वाधीन देश के रूप में अपने पूरे विकासकाल में उस एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के भीतर और बाहर भी अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रियता से संलिप्त रहा है जिसका कि वह हिस्सा है।

केवल अपनी भू-भौतिक स्थिति (geo-physical profile) के कारण ही नहीं, बल्कि अपनी अधोस्थित अवस्थिति के कारण भी, ऑस्ट्रेलिया अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में संलिप्त हुए बगैर नहीं रह सका। एक द्वीपीय देश होने के नाते, ऑस्ट्रेलिया के पास औसत खनिज और कृषि संसाधन हैं और इसके महाद्वीपीय आकार की तुलना में इसकी आबादी भी कम है। इसके इतिहास और विकास का सम्बन्ध लम्बे समय से इंग्लैण्ड और पाश्चात्य सभ्यता से रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया शक्ति केन्द्रों से दूर स्थित है। इन सभी कारकों के फलस्वरूप, ऑस्ट्रेलिया को अलग-अलग समय पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में धीरे-धीरे प्रवेश करने का प्रयास करना पड़ा है। इसलिए, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के साथ अपनी ऐतिहासिक घनिष्ठता और सम्पर्क के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया ने एशिया के राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक मामलों में अत्यधिक सक्रियता बनाई है। यही नहीं, इसकी जीवन्त (vibrant) अर्थव्यवस्था, औसत आकार की होते हुए भी, हाल के वर्षों में व्यापार और वित्त के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह में गहराई से जुड़ रही है।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आपः

- एशिया-प्रशान्त के देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक और सुरक्षा सम्बन्धी अंतर्क्रिया (interaction) को समझ सकेंगे;
- इस तथ्य का विश्लेषण कर सकेंगे कि एशियाई देशों के साथ अपनी अंतर्क्रिया को अधिकाधिक महत्व देने के कारण, ऑस्ट्रेलिया तो यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने घनिष्ठ सांस्कृतिक और सामरिक संपर्कों को भी बनाकर रख रहा है;
- राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के प्रति स्थाई प्रतिबद्धता (abiding commitment) सहित उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य तंत्र जैसे व्यापक लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक संस्थाओं के क्षेत्रों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पाई जाने वाली समानताओं को रेखांकित कर सकेंगे;
- यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्धों को स्थापित करने में ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती रूचि की विवेचना करने के साथ–साथ यह समीक्षा कर सकेंगे कि अब वह यूरोप और उत्तरी अमेरिका से अपने आपको आगे देखना चाहता है;
- शीत युद्ध के बाद विश्व के मामलों में एक स्वाधीन विदेश नीति और रुख अपनाने के ऑस्ट्रेलिया के प्रयासों का विश्लेषण कर सकेंगे; और
- एक साझे लक्ष्य के प्रति ऑस्ट्रेलिया की द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुसांस्कृतिक नीति और आपसी सहायक उपायों की समीक्षा कर सकेंगे।

1.3 ऑस्ट्रेलिया की घरेलू शक्तियाँ

ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक वर्गों ने पिछले कुछ दशकों में इस बात को अधिकाधिक समझा है कि उनके देश की सुरक्षा और समृद्धि बाहरी दुनिया के साथ उसकी राजनीतिक, रक्षा और गुप्तचर तंत्र सम्बन्धी भागीदारी की गुणवत्ता शक्ति (मज़बूती) पर निर्भर करती है। ऑस्ट्रेलिया का व्यावसायिक समुदाय भी पूरे विश्व में आर्थिक सम्पर्क बनाने की आवश्यकता को समझता है। इस प्रयास में, ऑस्ट्रेलिया के घोषित मूल्यों, इसकी सामाजिक–राजनीतिक संस्थाओं की अंतर्निहित शक्ति और विविधतापूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क बनाने की इसकी सामूहिक पहल ने देश के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय अनिश्चितता और आर्थिक भूमंडलीकरण के दौर में, तेज़ी से आगे बढ़ने की राह आसान की है। यह इतनी अधिक आसान रही है कि आज इसकी विदेश और व्यापार नीति का समग्र ढाँचा स्पष्ट रूप में वैश्विक दिखाई देता है, जिसमें इसके विविधतापूर्ण और विभिन्न हित तथा रिश्ते परिलक्षित होते हैं। हालांकि इसके कुछ हित इसके भूगोल से निर्धारित होते हैं किन्तु, इसके अन्य हित समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से निर्धारित हुए हैं। यही कारण है कि इसके प्रमुख रिश्तों का महत्व बदल रहा है जबकि अन्य रिश्ते अपेक्षाकृत स्थिर बने हुए हैं।

विदेश नीति सम्बन्धी पहल और दृष्टिकोणों के क्षेत्र में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, कम से कम कुछ संदर्भों में, कुछ उल्लेखनीय समांतर स्थितियाँ देखी जा सकती हैं। राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के प्रति प्रगाढ़ आस्था (abiding faith) और प्रतिबद्धतायुक्त एक उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य तंत्र विकसित कर लेने के कारण, विदेश नीति के संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया के वचनबद्ध उद्देश्य भारत जैसे ही हैं। 1901 में ही बन गए उसके संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्य, कानूनी व्यवहार और राजनीतिक संस्थाएँ इसकी विदेश नीति के आधार

हैं। इसके अतिरिक्त, विश्व भर में अन्य उदारवादी लोकतंत्रों के साथ काम करने की परम्परा बना लेने के कारण, ऑस्ट्रेलिया के नीतिगत कदम ऐसे मूल्यों और संस्थाओं की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने की ओर प्रवृत्त हैं।

साथ ही, भारत के समान ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक संस्थाएँ और परंपराएँ निस्संदेह संवेदनशील, दमदार और विकेन्द्रीकृत हैं। बहस जबरदस्त है, संचार माध्यम स्वतंत्र और सक्रिय हैं, और सत्ता तथा प्रभाव का वितरण व्यापक है। भारत की तरह, ऑस्ट्रेलिया ने वर्षों में जो संसदीय प्रकार की शासन प्रणाली विकसित की है, वह उसकी विदेश और व्यापार नीतियों के लिए बहस का एक प्रभावी मंच प्रदान करती है। अधिकांश सक्रिय लोकतंत्रों की तरह, जिन नीतियों के द्वारा आने वाली सरकारें राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाती है, वे नीतियाँ, अन्य बातों के अलावा, राजनीतिक वर्ग द्वारा संजोए और समर्थित मूल्यों से आकार ग्रहण करती हैं। इनमें से, उल्लेखनीय मूल्य हैं – कानून का राज और देश के सभी नागरिकों को अवसर की समानता। ये मूल्य विश्व भर में मानवाधिकार और मानव सुरक्षा की बेहतरी के लिए ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न प्रयासों के मूल में हैं।

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया तो एशिया-प्रशान्त क्षेत्र में अवस्थित एक पश्चिमी देश है, जिसके उत्तरी अमेरिका और यूरोप के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हैं और जिसका इतिहास पूरे एशिया में सक्रिय संलिप्तता का इतिहास है। किन्तु, हाल के दशकों में, ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति में एशिया के देशों के साथ और भी अधिक घनिष्ठ सम्बन्धों को प्राथमिकता दी गई है।

एशियाई देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया की सक्रिय साझीदारी के कारणों को आसानी से समझा जा सकता है। आज, कम से कम आठ एशियाई देश ऑस्ट्रेलिया के दस सबसे बड़े निर्यात बाज़ारों का रूप ले चुके हैं – इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैण्ड, ताईवान, चीन, कोरिया, जापान और भारत - हालाँकि वे इसी क्रम में महत्वपूर्ण नहीं हैं। हाल के वर्षों में, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के निर्यातों में छठाँ स्थान बना लिया है। साथ ही, यही एशियाई देश - जिनमें चीन, जापान और भारत महत्वपूर्ण हैं - पूँजी और निवेश के महत्वपूर्ण स्रोत, प्रमुख सुरक्षा भागीदार और कुशल प्रवासियों के बढ़ते स्रोत भी हैं। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि एशिया की कमज़ोरियाँ और शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन महत्वपूर्ण एशियाई संपर्कों के बावजूद, संयुक्त राज्य अमेरिका ही ऑस्ट्रेलिया के सुरक्षा सम्बन्धों के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है और उस हद तक यह पश्चिमी गठबंधन व्यवस्था में लगातार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता चला आ रहा है।

एक ओर एशिया के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध, तथा दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई समाज एवं उसकी संस्थाओं की पश्चिमी बनावट तथा बृहत्तर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध - अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के इन दो क्षेत्रों के बीच एक फलदायी परस्पर क्रिया को बनाए रखना ही ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति के स्पष्ट निर्धारक लक्षण हैं। चुनौती चाहे कितनी भी हो – कुछ मौकों पर इन चुनौतियों ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़र में ऑस्ट्रेलिया की साख को धक्का पहुँचाया है । हाल के दशकों में, ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी गठबंधन व्यवस्था के अवशेषों से मुक्त होकर विश्व के मामलों में एक स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करता रहा है। और इसलिए, इस परस्पर क्रिया का दक्षता से प्रबंधन करना उसकी विदेश नीति का एक प्रमुख विषय रहा है। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सुप्रबंधित स्थिति में यह परस्पर क्रिया तो शक्ति है, ऐसा खेल नहीं जिसमें जीतने वाले का फायदा और हारने वाले का नुकसान होता है। यही कारण है कि विदेश नीति तंत्र बार-बार यह जताने की चेष्टा करता है कि एशिया और विश्व के अन्य हिस्सों के साथ ऑस्ट्रेलिया के सम्पर्क दोनों पक्षों को मज़बूती देने वाले हैं क्योंकि वे किसी भी रिश्ते में जो कदम आगे बढ़ाते हैं वह दूसरों की कीमत पर नहीं होता। सीधे-सीधे कहा जाए, तो नीति का तार्किक आधार इतना ही मज़बूत है और एशिया के बाहर उसके सम्पर्क और भी विविध हैं। जैसे, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इसका रक्षा और गुप्तचरी सम्बन्धी गठबंधन एशिया में उसे और भी अधिक प्रभावशाली बनाता है।

इसी प्रकार, ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक अवस्थिति, एशियाई देशों के साथ व्यवहार और समझ पर इसका ज़ोर, और विश्व की एक सर्वाधिक एशिया-उन्मुख अर्थव्यवस्था के तौर पर उसकी स्थिति – ये सभी यूरोप और संयुक्त

राज्य अमेरिका के साथ उसके सम्बन्धों के सकारात्मक गुण हैं। हालाँकि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय भागीदारों के एशियाई देशों के साथ अपने स्वयं के सुविकसित सम्पर्क हैं, फिर भी वे एशिया में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका और उसके अद्वितीय परिप्रेक्ष्य को कम नहीं आँकते। यह इस हद तक है कि उत्तरी गोलार्ध की अनेकानेक कम्पनियों ने ऑस्ट्रेलिया में अपने एशियाई मुख्यालय बना लिए हैं, और इसका कारण है एशिया के साथ इसकी निकटता तथा उसके एशियाई कौशलों की गहनता तथा निवेश का वातावरण।

आने वाले वर्षों में, एशिया के साथ ऑस्ट्रेलिया का घनिष्ठ जुड़ाव बना रहेगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया और एशिया के विभिन्न देशों के बीच कोई खास राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मतभेद नहीं हैं, जैसे कि क्षेत्र के अनेक देशों के बीच आपस में ही अच्छे-खासे मतभेद हैं। इसलिए, आने वाले वर्षों में, इस बात की संभावना है कि ऑस्ट्रेलिया उन सुरक्षा सम्बन्धी और आर्थिक हितों पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा जो उसके मौजूदा एशियाई जुड़ाव को सहारा देते हैं।

1.4 क्रियात्मक बंधुत्व के माध्यम से गठबंधन निर्माण

भूगोल कभी भी ऑस्ट्रेलिया के अन्तर्राष्ट्रीय संपर्कों का एकमात्र निर्धारक नहीं रहा। एक ऐसे विश्व में, जहाँ भूमंडलीय आर्थिक एकीकरण जारी रहने की संभावना है, जिसमें दूर काम कर रहे छोटे गैर-राष्ट्रीय समूहों से सुरक्षा को खतरा हो सकता है, ऐसे विश्व में ऑस्ट्रेलिया मानता है कि उसे अपने हितों को विश्व में फैलाना होगा। ये प्रवृत्तियाँ ज़ारी रहेंगी, तो ऑस्ट्रेलिया अपने आपको इस स्थिति में अधिकाधिक पाएगा जहाँ उसे अपनी विदेश और व्यापार नीति पर भौगोलिक संदर्भ में कम और विशिष्ट हितों की साझेदारी वाले देशों तथा देश-समूहों के साथ विकसित होती क्रियात्मक बंधुता के संदर्भ में अधिक विचार करना होगा। इन्हीं उद्देश्यों से, ऑस्ट्रेलिया हाल के वर्षों में क्षेत्र के भीतर और बाहर गठबंधन बनाने की पहल करता रहा है।

उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया देशों के एक छोटे समूह के साथ घनिष्ठ गुप्तचर सम्पर्क रखता है जिनके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में भिन्न-भिन्न क्षेत्रीय फ़ोकस हैं। ऑस्ट्रेलिया गुप्त सूचनाओं के संग्रह और साझेदारी के क्षेत्र में उस भागीदारी को जारी रखता है जो उसने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, इंगलैण्ड, कनाडा और न्यूज़ीलैण्ड के साथ बनाई थी। इस सम्बन्ध का आधार सामरिक बंधुता (सम्बन्ध) और अलग-अलग राष्ट्रों के हितों की रक्षा के लिए विश्वसनीय गुप्तचर सूचना प्राप्त करने का साझा हित है। यह एक-दूसरे पर भरोसे और आवश्यक संसाधनों तथा क्षमताओं के स्वामित्व पर भी आधारित है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में गुप्त सूचनाओं का संग्रह और भी अहम् हो जाने के कारण उस साझा हित के बढ़ने की संभावना है, और शायद इसके चलते और भी देशों के साथ सहयोग किया जाएगा।

अपनी सुरक्षा नीतियों के समांतर, ऑस्ट्रेलिया व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता; गैट (General Agreement on Tariff and Trade; GATT) और एशिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग – एपेक (APEC) जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में बहुपक्षीय मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने में काफी सक्रिय रहा है। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि व्यापार नीति के ऐसे दो प्रमुख प्रवर्तनकारी उपाय थे जिन्हें ऑस्ट्रेलिया ने 1980 के दशक में लागू किया। इस दिशा में, ऑस्ट्रेलिया ने उस समूह का प्रारंभ और नेतृत्व किया जिसे बाद में (1986 में स्थापित) उचित कृषि व्यापार राष्ट्रों के कैर्न्स समूह के नाम से जाना गया। पॉच महाद्वीपों के कम से कम तेरह अन्य देश कैर्न्स समूह के सदस्य हैं। ये हैं : अर्जेन्टीना, ब्राजील, चिली, कोलम्बिया और उरुग्वे (लैटिन अमेरिका में); इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैण्ड और फिलीपींस (एशिया में), ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड और फिज़ी (ऑस्ट्रेलिया में), कनाडा (उत्तरी अमेरिका में); और हंगरी (यूरोप में)। कैर्न्स समूह का उद्देश्य था - उरुग्वे बातचीत के दौर के लिए गैट (GATT) की कार्यसूची में कृषि को सम्मिलित करना और तत्पश्चात् कृषि नीतियों में सुधार करना, विशेषकर निर्यात अनुदान (सब्सिडी), आयात उपलब्धता और आंतरिक सहायता जैसे तीन विवादित क्षेत्रों के संदर्भ में प्रमुख

औद्योगीकृत अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों में सुधार करना। सौदेबाजी के उद्देश्य से, ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में, कैर्न्स समूह ने कृषि व्यापार में सुधार की माँग की और उसमें सफलता भी प्राप्त की। इस प्रकार, कैर्न्स समूह के रूप में ऑस्ट्रेलिया की पहल एक रचनात्मक और प्रभावी बहुपक्षीय कूटनीति का प्रतीक है जिसने सदस्यों के विषम समूह को एकजुट कर दिया, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बातचीत की और एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया के लिए एकजुट किए हुए हैं।

1.5 बहुपक्षीयता से द्विपक्षीयता की ओर

अलग-अलग राष्ट्र-राज्यों और उनकी सरकारों की कार्रवाइयाँ विश्व की सुरक्षा और उसके आर्थिक परिवेश पर अब भी सबसे अधिक प्रभाव डालती हैं। इसलिए, ऑस्ट्रेलिया अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए विश्व-भर में अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों की शक्ति पर निर्भर करता है। ऑस्ट्रेलिया की व्यापार और विदेश नीति के दिन-प्रतिदिन के कार्य का एक बृहत्तर हिस्सा द्विपक्षीय पक्ष–समर्थन में निहित है – अर्थात् सरकारों और दूसरों को इस बात के लिए प्रभावित करने के लिए काम करना कि वे ऐसे निर्णय करें जो ऑस्ट्रेलिया के हित में भी हों और उनके हित में भी।

द्विपक्षीय पक्ष–समर्थन और सहयोग तो भूमंडलीय और क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए बुनियादी तौर पर जरूरी हैं। उदाहरण के लिए, उरुग्वे बातचीत के दौरान की बहुपक्षीय व्यापार पर बातचीत के बाज़ारी उपलब्धता सम्बन्धी परिणाम अनिवार्य रूप में द्विपक्षीय समझौतों की एक शृंखला है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, ऑस्ट्रेलिया का एक मुख्य उद्देश्य है – दूसरे देशों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे कानूनों को दुरुस्त करें और आतंकी गुटों को रोकने और उनसे निपटने के लिए क्षमताओं का विकास करें। ऑस्ट्रेलिया की द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय नीतियाँ एक साझा ध्येय की दिशा में एक परस्पर सहायक साधन हैं – अर्थात् राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाना। वे एक-दूसरे के विकल्प नहीं हैं।

प्राथमिकताओं के बारे में किए गए निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ऑस्ट्रेलिया के सभी द्विपक्षीय सम्बन्ध उसके लिए समान रूप में महत्वपूर्ण नहीं हैं। सभी क्षेत्रीय सम्बन्ध अथवा बहुपक्षीय गतिविधियाँ ऑस्ट्रेलियावासियों की संपन्नता और सुरक्षा में बढ़ोतरी नहीं करेंगी। संयुक्त राष्ट्र में, अन्य सभी सदस्यों की तरह, ऑस्ट्रेलिया सही विकल्पों पर काम करता है और उन मुद्दों पर अपनी कोशिशें करता है जो उसके हितों के अनुरूप होते हैं। विशाल और बढ़ती अन्तर्राष्ट्रीय कार्यसूची वाले एक जटिल और अस्थिर विश्व में, प्रत्येक देश को इस बारे में व्यावहारिकता और साफ दृष्टि से काम लेना होता है कि कौन-से रिश्तों, कौन-से मुद्दों और कौन-सी बहुपक्षीय गतिविधियों से राष्ट्रीय हित के आगे बढ़ने की सर्वाधिक संभावना है। इस संदर्भ में, ऑस्ट्रेलिया अन्य देशों से बिल्कुल भी भिन्न नहीं है।

1.6 ऑस्ट्रेलिया के अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्पर्क

ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की मज़बूती और घरेलू शक्ति ने उसे इस स्थिति में ला दिया है कि वह अधिकाधिक वैश्विक और अस्थिर अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश की चुनौतियों से कारगर ढंग से निपट सकता है। देश की राष्ट्रीय आर्थिक उपलब्धि और अन्य घरेलू शक्तियों का उसकी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और दबदबे पर बहुत असर पड़ा है।

ऑस्ट्रेलिया की संभावनाएँ हमेशा उसके अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संपर्कों पर निर्भर रही हैं। इसकी अधिकांश संपदा का आधार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश है। ऑस्ट्रेलिया के खनन और कृषि उद्योगों का विकास अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक उनकी पहुँच के कारण हुआ। ऑस्ट्रेलिया का घरेलू औद्योगीकरण अधिकतर विदेशी निवेश और उससे होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण संभव हुआ है।

पिछले दो दशकों में, ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और निवेश सम्पर्क व्यापक आर्थिक सुधार के परिणामस्वरूप मज़बूत हुए हैं। व्यापार की राह की बाधाएँ हटा दी गई हैं। व्यापक सुधारों ने उत्पादकता बढ़ा दी है। ऑस्ट्रेलिया में 1990 के दशक के दौरान उत्पादकता की वृद्धि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में फिनलैण्ड के बाद शीर्ष स्तर पर थी। जिन कारकों ने निवेश को प्रोत्साहित किया है, वे हैं : अनियमन (deregulation), कर सुधार, प्रतियोगिता सम्बन्धी नीतियों को मज़बूत करना, अधिक लचीला श्रम बाज़ार, आधारभूत संरचना (बुनियादी सुविधाओं) का अधिक सक्षम प्रावधान, और निम्न तथा प्रत्याशित मुद्रास्फीति दर। इन सुधारों के परिणामस्वरूप होने वाली मज़बूत आर्थिक उपलब्धि ने ऑस्ट्रेलिया की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को ऊँचा उठा दिया है। और आज ऑस्ट्रेलिया दुनिया की एक सबसे अच्छा कार्य करने वाली विकसित अर्थव्यवस्था है। पिछले दशक में इसके सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product; GDP) में औसतन चार प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है, जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष स्थानों में से है।

निजीकरण, निगमित शासन (Corporate governance) और कर सुधारों ने ऑस्ट्रेलिया के पूँजी बाज़ार को अधिक विशाल बनाने में मदद की है और साझा स्वामित्व को सुगम किया है। इन सुधारों ने ऑस्ट्रेलिया में अधिक अन्तर्राष्ट्रीय निवेश को भी प्रोत्साहित किया है, जिससे इसके पूँजी बाज़ारों में और भी अधिक गहराई आई है। विश्व के शेयर अथवा इक्विटी बाज़ारों में ऑस्ट्रेलिया का स्थान बढ़कर नौवाँ हो गया है, जिसके फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय निवेशक ऑस्ट्रेलिया के पूँजी बाज़ारों में अधिक मात्रा में अपना धन निवेश कर रहे हैं। इससे कारोबार के लिए उधार लेने की लागत कम हो गई है और नकदी (liquidity) में और बढ़ोत्तरी हुई है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में ऑस्ट्रेलिया का बढ़ता एकीकरण और उससे आने वाली समृद्धि अथवा संपन्नता व्यापार प्रवाह और वित्त को संरक्षित और संवर्धित करने वाले स्थिर और मुक्त नियमों और व्यवस्थाओं पर निर्भर करती है। इसलिए, सरकार विश्व व्यापार संगठन और द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के माध्यम से ऑस्ट्रेलियाई निर्यातकों के समक्ष आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए काम करती है। यह अन्य सरकारों के साथ मिलकर वैश्विक व्यापार और वित्त व्यवस्थाओं की स्थिरता और मज़बूती को सुनिश्चित करने के लिए और एक अधिक मुक्त तथा पारदर्शी वैश्विक व्यावसायिक वातावरण बनाने के लिए काम करती है।

1.7 ऑस्ट्रेलिया के सुरक्षा सम्पर्क

ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा अधिकतर उसकी प्रमुख गठबंधनों और रक्षा खुफिया तंत्र तथा पुलिस सम्बन्धी भागीदारियों की गुणवत्ता और मज़बूती पर निर्भर करती है। ऑस्ट्रेलिया की सशक्त सुरक्षा क्षमताओं ने इस क्षेत्र के भीतर और बाहर स्थित देशों से निपटने के प्रति इसके आत्मविश्वास को मज़बूत किया है। देश की प्रौद्योगिकीय स्तर पर उन्नत सशस्त्र सेनाओं ने ऑस्ट्रेलिया को एशिया तथा दक्षिण प्रशान्त क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण और मान्य सैन्य शक्ति बना दिया है। पूर्वी तिमोर में अन्तर्राष्ट्रीय कार्रवाई के उसके निर्णायक और प्रभावी नेतृत्व ने तथा आतंकवाद विरोधी लड़ाई में उसके योगदान की व्यापकता ने केवल अन्तर्राष्ट्रीय ध्यान को ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय सहायता को भी आकर्षित किया है।

आतंकवाद विरोधी लड़ाई ने, विशेषकर एशियाई देशों के साथ, ऑस्ट्रेलिया के अन्य रक्षा तथा कानून प्रवर्तन सम्बन्धी रिश्तों के महत्व को रेखांकित किया है। बाली में हुए आतंकी हमलों की संयुक्त जाँच में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच बहुत अच्छे सहयोग ने इस तरह के संपर्कों की अहमियत अथवा महत्व को दिखा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल के वर्षों में इन रिश्तों को और भी मज़बूत करने का प्रयास किया है। इनसे सुरक्षा मुद्दों पर, विशेषकर आतंकवाद, अन्तर्राष्ट्रीय अपराध और जनसंहार के हथियारों के प्रसार जैसे मुद्दों पर सहयोग करना सुगम हो जाता है; और हम ऐसे खतरों के खिलाफ क्षेत्रीय देशों की क्षमताओं को बढ़ाने की स्थिति में आ जाते हैं। और व्यापक प्रशिक्षण, द्विपक्षीय संवाद (bilateral dialogues), संयुक्त अभ्यासों तथा गुप्त सूचनाओं के आदान-

प्रदान से रक्षा मुद्दों पर अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है, जिससे गलतफहमी और विवाद का जोखिम कम हो जाता है।

1.8 ऑस्ट्रेलिया-भारत अभिसरण

हाल के वर्षों में, दोनों देशों के बीच भू-राजनीतिक अभिसरण (Convergence) का विकास देखने को मिला है। इनके बीच केवल मिलते-जुलते सामरिक सुरक्षा हितों की परस्पर मान्यता ही विद्यमान नहीं है बल्कि सीधे द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सुरक्षा मंचों में जुड़ने की इच्छा भी व्यापक रूप से मौजूद है। इन तथ्यों का संज्ञान लेते हुए, ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों ने ही वर्ष 2001 में सामरिक संवाद की एक शृंखला की शुरुआत की थी। इस शृंखला में क्षेत्रीय और समुद्री मामलों के साथ–साथ सामारिक तथा रक्षा योजना जैसे अनेक व्यापक मुद्दों को शामिल किया गया।

इसके कारण स्पष्ट हैं। एक तो यही कि आज विश्व का आधा समुद्री व्यापार मलक्का (Malacca) और लोम्बोक जलडमरू–मध्य (Lombok Straits) के माध्यम से होता है जिसमें दोनों ही देशों के व्यापार की मात्रा कम महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरे यह कि इंडोनेशियाई द्वीप समूह (archiapelago) के असंख्य टापू हथियार के सौदागरों और चोरी के माल के व्यापारियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं। इसलिए, व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए समुद्री मार्गों की रक्षा करना और नशीले पदार्थों तथा मानव तस्करी रोकने के लिए समुद्र में गश्त लगाना इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों के लिए जरूरी है।

भारत ने 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण की जो शुरुआत की थी उससे द्विपक्षीय सम्बन्धों में विकास को गति मिली है। 1990 के दशक में हुई आर्थिक सुधारों की शुरुआत ने व्यापार को फिर से सक्रिय करने में मदद की है और उसके परिणामस्वरूप द्विपक्षीय व्यापार के सापेक्ष महत्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। भारत को होने वाले प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई निर्यातों में अमौद्रिक सोना, कोयला, तांबे का अयस्क, और ऊन शामिल हैं। भारत कुकिंग कोयले के लिए ऑस्ट्रेलिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार है। हाल के वर्षों में, ऑस्ट्रेलिया से खनन उपकरण तथा विद्युत यंत्रों समेत तथाकथित विस्तृत ढंग से रूपांतरित विनिर्माण के निर्यात में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई है। भारत से ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आयातों में मोती और रत्न और वस्त्र शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया से तापीय कोयले, कुकिंग कोयले और संभवतः गैस और फल तथा सब्जी और गेहूँ जैसे कृषि निर्यात की संभावनाएँ हैं। कैनबरा में अब यह अधिकाधिक माना जाने लगा है कि ऑस्ट्रेलिया की अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति के लिए भारत के आर्थिक उत्थान के महत्वपूर्ण निहितार्थ होंगे। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति के संदर्भों में यह प्रवृत्ति पहले ही दिखाई देने लगी है। भारत ने – कुछ अन्य प्रमुख विकासशील देशों के साथ – दोहा दौर (Doha Round) की बातचीत के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार पर बातचीत करने वालों को भारत तथा अन्य प्रमुख उभरते बाज़ारों के विचारों को बहुपक्षीय व्यापार सम्बन्धी बातचीत में ध्यान में रखना होगा और उससे भी कार्यनीति पर असर पड़ेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व वाले कैर्न्स समूह की भावी भूमिका भी शामिल है।

11 सितम्बर की घटना के बाद, कैनबरा आतंकवाद द्वारा खड़े किए गए खतरे को अच्छी तरह से समझता है। संयुक्त राज्य अमेरिका नेतृत्व में गठबंधन के सदस्य के रूप में खाड़ी युद्ध में उसकी भागीदारी से ऑस्ट्रेलिया के सरोकार स्पष्ट तौर पर और भी बढ़ गए हैं। अतीत में, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के इस दावे पर कभी विश्वास नहीं किया था कि "सीमा-पार" आतंकवाद उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरा है। किन्तु, बाली विस्फोट के बाद हुए एक के बाद एक आतंकी हमलों ने ऑस्ट्रेलिया को अपना दृष्टिकोण बदलने को बाध्य कर दिया है। उसकी सरकार ने जुलाई 2004 में श्वेत–पत्र जारी किया जिसमें उसने इस बात को माना कि राष्ट्रीय सीमाएँ अब स्पष्ट तौर पर आतंकी खतरे को परिभाषित नहीं कर सकतीं क्योंकि आतंकवाद सचमुच एक

अन्तर्राष्ट्रीय परिघटना है। इस बीच 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने क्षेत्र के अन्य देशों की तरह भारत के साथ भी, आतंकी गतिविधियों की निगरानी और गुप्त सूचनाओं की साझेदारी के लिए, एक सहमति ज्ञापन–पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किए। मार्च 2006 के प्रारंभ में, अनेक विषयों से सम्बन्धित अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें से, एक उल्लेखनीय समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन–पत्र है जिसमें सुरक्षा तथा रक्षा सम्बन्धी मामलों, प्रशिक्षण, समुद्री सहयोग, रक्षा उद्योगों, रक्षा अनुसंधान और विकास पर विचारों के आदान-प्रदान से सम्बन्धित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इस ज्ञापन–पत्र में दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग के दिग्दर्शन और निगरानी के लिए 'रक्षा सम्बन्धी भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह' की स्थापना का भी प्रावधान है। द्विपक्षीय रक्षा सम्बन्ध बनाने के हाल के ये ऑस्ट्रेलिया प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

1.9 सारांश

ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त में गहराई से संलिप्त है – चाहे वह यूरोप में हो या एशिया में। ऑस्ट्रेलिया बाहरी विश्व के साथ राजनीतिक, रक्षा और खुफिया तंत्र सम्बन्धी भागीदारी की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है और उसकी जरूरत को भी पहचानता है। एक ओर एशिया के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध तथा दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई समाज तथा उसकी संस्थाओं की पश्चिमी बनावट एवं बृहत्तर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध - अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के इन दो क्षेत्रों के बीच एक फलदायी परस्पर क्रिया को बनाए रखना ही ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति के स्पष्ट निर्धारक लक्षण हैं। ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी गठबंधन व्यवस्था के अवशेषों से मुक्त होकर विश्व के मामलों में एक स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करता रहा है। ऑस्ट्रेलिया अपने आपको उस स्थिति में अधिकाधिक पाएगा जहाँ उसे अपनी विदेश और व्यापार नीति पर भौगोलिक संदर्भ में कम और विशिष्ट हितों की साझेदारी वाले देशों तथा देश-समूहों के साथ विकसित होती, क्रियात्मक बंधुता के संदर्भ में अधिक विचार करना होगा। गैट और एपेक व्यापार नीति के ऐसे दो प्रमुख प्रवर्तनकारी उपाय थे जिन्हें ऑस्ट्रेलिया ने 1980 के दशक में लागू किया। ऑस्ट्रेलिया अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए विश्व–भर में अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों की शक्ति पर निर्भर करता है। ऑस्ट्रेलिया की द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय नीतियाँ साझा ध्येय की दिशा में एक परस्पर सहायक साधन है – अर्थात् राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाना।

ऑस्ट्रेलिया आज विश्व की एक सबसे अच्छा काम करने वाली विकसित अर्थव्यवस्था है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में ऑस्ट्रेलिया का बढ़ता एकीकरण और उससे आने वाली संपन्नता तो व्यापार प्रवाह और वित्त को संरक्षित और संवर्धित करने वाले स्थिर और मुक्त नियमों और व्यवस्थाओं पर निर्भर करती है। इसलिए, सरकार ऑस्ट्रेलियाई निर्यातकों के समक्ष आने वाली बाधाओं को विश्व व्यापार संगठन और द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के माध्यम से दूर करने के लिए काम करती है। ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा अधिकतर उसके प्रमुख गठबंधनों और रक्षा, खुफिया तंत्र तथा पुलिस सम्बन्धी भागीदारियों की गुणवत्ता और मज़बूती पर निर्भर करती है। ऑस्ट्रेलिया की सशक्त सुरक्षा क्षमताओं ने इस क्षेत्र के भीतर और बाहर स्थित देशों से निपटने के प्रति इसके आत्मविश्वास को मज़बूत किया है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच भू-राजनीतिक अभिसरण का विकास स्पष्ट रूप से देखने का मिला है।

1.10 अभ्यास

1) ऑस्ट्रेलिया की घरेलू शक्तियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

2) हाल के वर्षों में एशिया-प्रशान्त क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति का आकलन कीजिए।

3) 1990 के दशक से ऑस्ट्रेलिया और भारत के आपसी आर्थिक और सुरक्षा सम्बन्धों की विवेचना कीजिए।

1.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

फॉरवर्ड, रॉय (संपा.) *पब्लिक पॉलिसी इन ऑस्ट्रेलिया* (मेलबार्न : चेशयर, 1974)।

ट्रूड, रस्सेल (संपा.) *दि मेकिंग ऑफ ऑस्ट्रेलियन फॉरेन पॉलिसी* (ब्रिसबेन : ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी, 1997)।

मेडियनस्की, एफ. (संपा.) *ऑस्ट्रेलियन फॉरेन पॉलिसी इनटू दि न्यू मिलिनियम* (साउथ मेलबर्न : मैकमिलन, 1997)।

स्मिथ, ग्रे, डेव कॉक्स एवं स्कॉट बर्चिल, *ऑस्ट्रेलिया इन दि वर्ल्ड : एन इंट्रोडक्शन टू ऑफ ऑस्ट्रेलियन फॉरेन पॉलिसी* (मेलबर्न : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2001)।